सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका

श्रीमती प्रीती
असि0 प्रो0
समाजशास्त्र विभाग
एस. एस. कॉलेज, शाहजहाँपुर

शोध सारः— भारत विशेष रूप से अपनी समृद्धि और विकास के लिए प्रयासरत रहा है। भारत ने अपने विकास के लिए अनेक योजनाओं का कार्यन्वयन भी किया है और समृद्धि की दिशा में नयें कदम उठायें है। इसमें कुशल नेतृत्व, राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन और जन भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है जैसे—विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान एवं अर्थव्यवस्था की दिशा में काम और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि इसके सतत् विकास के प्रमुख पहलूओं में शमिल है। सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई है जो गरीबी, बेरोजगारी, और सामाजिक असामनता को कम करने के लक्ष्य को ध्याान में रखती है देश मे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई है जिसमे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का भी अहम योगदान है।

भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र मे भी ध्यान दिया जा रहा है। देश में जल, ऊर्जा और पर्यावरण के मामले में भी सकारात्मक पहलूओं की ओर कदम बढ़ाए है।

इस प्रकार भारत ने अपने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे सकारत्मक परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाए ह। भारत अपने नागरिकों को समृद्धि की दिशा में एक सशक्त, समृद्ध और सामरिक रूप से जावबदेह नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तब भारत एक विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा ।

मुख्य शब्द— सार्वभौमिक, सहस्त्राब्दि, वैश्विक, संसाधन, समावेशी, गुणवत्तायुक्त ।

प्रस्तावना— सर्वप्रथम 1987 में ब्रंटलैण्ड कमीशन रिपोर्ट में पहली सतत् विकास की व्याख्या की गई थी। ब्रंटलैण्ड रिपोर्ट के संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। और निकोला टेस्ला सतत् विकास के जनक थे। सतत् विकास के तीन स्तम्भ है—वे है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज।

सतत् विकास से हमारा तात्पर्य ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्कताएँ पूरी करें । सतत् विकास एक दूरदर्शी योजना है। जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है।

सतत् विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित करना है। जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्धि सम्भव हो सकें। इस अवधारणा को ''विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।''

उदाहरण के लिए–जब हम तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते है तो हमें इस तरह करने की आवश्यकता होती है जिससे हमारे पर्यावरण या समाज को नुकसान न पहुँचे। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन बचा है, और सभी को इन संसाधनों तक उचित पहुँच मिले यह सतत् विकास का मूल उद्देश्य है।

सतत् विकास सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2023 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सतत् विकास लक्ष्यों को एक सार्वभौमिक आह्यान के रूप में अपनाया गया था।

विदित हो कि 2000–2015 तक की अवधि के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals -MDG) की प्राप्ति की योजना बनायी गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 मे पूर्ण हो चुकी थी। उसके पश्चात आने वाले वर्षो के लिए एक नया एजेंडा (SDG-2030) को औपचारिक तौर पर सभी सदस्य राष्ट्रो ने अंगीकृत किया था। सतत् विकास लक्ष्यों की बात करने से पहले यह ज्ञात होना भी आवश्यक है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य क्या थे ?

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals -MDG)

1. भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना
3. लिंग समानता तथा महिला सशक्तीकरण को प्रचारित करना ।
4. शिशृ–मृत्यु दर घटना।
5. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ।
6. एच आई बी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना
7. पर्यावरण सतत्ता
8. वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना ।

भारत लक्षित लक्ष्यो में से एचआईबी/एड्स, गरीबी, सार्वभैमिक शिक्षा तथा शिशु मृत्य दर में अभी बहुत पीछे है हालांकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों के अन्तर्गत ही शामिल कर लिया गया है।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG)– 'ट्रॉस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्ड : द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेबलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत् विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है। भारत सहित '93 देशों ने सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया गया तथा 1 जनवरी 2016 को यह लागू हुआ। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हे 2016–2030 की अवधि में प्राप्त करना है। और इसमें से लक्ष्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिए गए है जिन्हे और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है।

सयुंक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030– संयुक्त राष्ट्र ने एजेंडा 2030 अपनाया, इसमें कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है–

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति ।
2. भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा ।
3. सभी उम्र के लोगो मे स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ्य जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना ।
5. लैंगिक समानता समाप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबन्धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना ।
8. सभी के लिए निरतंर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना ।
9. लचीला बुनियादी ढाँचा, समावेशी और सतत् औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ।
10. देशो के बीच मे असमानता को कम करना ।
11. सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना ।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावो से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना ।
14. स्थयी सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनो का संरक्षण और उपयोग करना ।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियो, सुरक्षित जंगलो और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना ।
16. सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण तथा समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हे प्रभावी जबाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके ।
17. सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना ।

सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के सन्दर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास–

भारत लम्बे समय से सतत् विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और इसके मूलभूत सिद्धान्तों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है।

भारत में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को समावेशी और सतत् विकास प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के रूप में अपनाया गया है। भारत ने एसडीजी के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गरीबी दर कम करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप गरीबी दर में गिरावट आयी हैं। जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले है। और भारत ने शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने, लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक विद्यालय नामांकन प्राप्त करने में भी प्रगति की है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। जिससे मातृ एवं 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में कमी आई है। स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच बढ़ी हैं। जिससे कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

इस सफलता में योगदान देने वाले कई कारकों में से सामाजिक पूंजी जो नेटवर्क रिश्तों और मानदंडो को संदर्भित करती है। जो सहयोग और सामूहिक कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है।

भारत ने एसडीजी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसने समुदायों को एक साथ आने, संसाधनों को साझा करने और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सक्षम बनाया। सामाजिक पूंजी ने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में भी मद्द मिली जो सतत् विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक पूंजी का लाभ उठाकर, भारत विभिन्न चुनौतियों से निपटने और एस डी जी को प्रभावी ढ़ग में हासिल करने के लिए व्याक्तियों, समुदायों और संगठनों के सामुहिक प्रयासों का उपयोग कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन करता है। भारत का एसडीजी सूचकांक रैंक 166 देशों में से 112 है। जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 63.5 प्रतिशत हैं।

भारत ने कई सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जैसे – भारत ने गरीबी दर कम करने में पर्याप्त प्रगति की है। सामाजिक पूँजी ने समुदाय–संचालित पहलों स्वयं सहायता समूहों और माइक्रोफाइनेंस नेटवर्क को सक्षम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हाशिए पर मौजूद आबादी को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करते है।

भारत ने भूख और कुपोषण को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सामाजिक पूंजी के माध्यम से किसानों की सहकारी समितियों और ज्ञान–साझाकरण नेटवर्क की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते है। पौष्टिक भोजन तक पहुँच में सुधार करते है और खाद्य सुरक्षा बढ़ाते है।

भारत ने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में। भारत ने गुणवत्तपूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किये है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, शिक्षा पहलों का समर्थन करने और बुनियादी ढाँचें, तथा शैक्षिक

परिणामों में सुधार करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने में सहायक रही हैं।

भारत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और महिलाओं की आवाज सुनने के लिए मंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जिससे आर्थिक सशक्तीकरण और लिंग समानता में वृद्धि हुई है। भारत ने टिकाऊ और समावेशी शहर और समुदाय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक पूंजी ने नागरिक जुड़ाव, भागीदारी योजना प्रक्रियाओं और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को सुविधाजनक बनाया है। जो टिकाऊ शहरी विकास अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया है। भारत ने व्यक्तियों को सतत् विकास प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सतत् विकास के कई आयामों को संबोधित करने और स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम रहा है।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) एजेंडा 2030 के महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी दूर करने के उद्देश्य पूर्ति के लिए सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता प्रदान की जा रही है । तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुरूप बनाए गए है जिनमें मेंक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी दोनो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शामिल है। इसके अलावा अधिक बजट आबंटनो से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी सामप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत ने सतत् विकास के लक्ष्यों के सन्दर्भ में ही विज्ञान, तकनीक और इफ्रांस्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधुनिक तकनीकी और अनुसंधान में निवेश के माध्यम से देश ने अपनी तकनीकी क्षमता मे वृद्धि की है जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है । भारत ने सामाजिक समृद्धि की दृष्टि से अपार संभावनाओं का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करने के लिए जन जागरूकता और सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। महिला शाक्ति, असमानता के खिलाफ लड़ाई और जनसंख्या नियन्त्रण की दिशा में कदम उठाने का प्रयास देश को समृद्धि की ऊँचाईयों तक पहुचाने मे सहायोग प्रदान कर रहा है।

भारत का सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समर्थन और सहयोग के माध्यम से देश ने अपने विकास को गति देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे आवश्यक सामरिक और आर्थिक संबंध बनायें है।

भारत ने आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से गॉवों में रोजगार सृष्टि करने का प्रयास किया है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य सेतू तथा सर्व–शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से आम लोगो को सस्ती और प्रभावी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के सन्दर्भ मे भारत की प्रगति का आकलन–

केन्द्र सरकार ने सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यन्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त

राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परषिद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक–ढाँचे के अन्तर्गत अपनाये जा सकते है। उसके पश्चात इससे जो परिणाम प्राप्त होगें उससे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा और यह भारत की प्रमुख उपलब्धियों जैसे–स्वच्छ भारत, वित्तीय समावेशन आदि को उजागर करेगा।

भारत सरकार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के लिए नागरिक समाज से भी सुझाव मांगे है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिक समाज संगठनों (CSO) के ये सुझाव सरकार की रिपोर्ट का हिस्सा होगें या नही ।

निष्कर्ष– हालॉकि भारत ने कई सतत् विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है । फिर भी 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद अपर्याप्त संसाधन, सीमित क्षमता, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, गरीबी और लैंगिक असामनता जैसे जटिल और परस्पर जुड़े मुद्दो के लिए समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक पूंजी सहयोग, ज्ञान साझाकरण और स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है। यह सामाजिक एकजुटता और समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है। लचीलापन बढ़ा सकता है और समुदायों के भीतर अनुकूली क्षमता बढ़ा सकता है। जिससे अन्ततः अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास हो सकता है। सरकार, नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न हितधारकों को शेष चुनौतियों का समाधान करने और एस डी जी सहयोग और पहल जारी रखने की आवश्यकता है।

भारत ने सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिससे देश ने अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और उनके अधिकारों की सुरक्षा में समर्थन प्रदान किया है। परन्तु फिर भी भारत को अभी बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत यदि सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता है तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो तथा साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा।

हमारे संघीय ढाँचे में सतत् विकास लक्ष्यों की सम्पूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । राज्यों मे विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है इन योजनओं का सतत् विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिए तथा केन्द्र व राज्य सरकारों को सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। इसके परिणामस्वरूप भारत यदि 2030 तक सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो भारत एक विकसित तथा समुद्ध राष्ट्र बन सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. सिंह रमेश, भारतीय अर्थव्यवस्था, MC Graw Hill, 2023
2. प्रो0 लाल एस0 एन0, डॉ0 लाल एस0 के0, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम पब्लिशर्स, 2015, अप्रैल
3. ओझा शिव कुमार, भारतीय अर्थव्यवस्थाःएक सम्रग अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन, 2013–2014 सितम्बर
4. लेखी आर0 के0, आर्थिक विकास व योजनाएँ, कल्याणी पब्लिशर्स

5- डॉ0 मिश्रा जे0 पी0, संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1960

6- प्रो0 ओझा बी0 एल0, विकास का अर्थशास्त्र, एस बी पी डी पब्लिकेशन्स

7- https://india.un.org

8- https://www.drishtiias.com

9- https://www.undp.org

10–योजना पत्रिका